

# खाद्य प्रसंस्करण की 51 नई परियोजनाओं को मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति (एसएलईसी) की बैठक में बुधवार को 51 नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कृषि उत्पादन आयुक्त एवं एसएलईसी अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजनाओं की प्रगति, नए निवेश प्रस्तावों, वित्तीय प्रोत्साहनों और उद्यमियों से जुड़े विभिन्न प्रकरणों पर चर्चा हुई।

स्वीकृत प्रस्तावों में फ्रोजन फल-सब्जी प्रसंस्करण, कैटल फीड, डिहाइड्रेटेड फल-सब्जियां, मिठाई-नमकीन, बेकरी, आइसक्रीम, पोटैटो फ्लेक्स, सोया उत्पाद, डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद, दाल और आटा प्रसंस्करण जैसी इकाइयां शामिल हैं। समिति ने महिला उद्यमी समूहों समेत विभिन्न इकाइयों द्वारा सौर ऊर्जा आधारित खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इनमें रेडी-टू-कुक खाद्य उत्पाद, आटा, मसाले, दाल व चावल मिल, सोया उत्पाद, ब्रेडक्रम्ब्स, फ्रूट जूस, कन्ड फल-सब्जियां और गुड़ आधारित इकाइयां शामिल हैं। ब्यूरो

उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति की बैठक



## उद्यमी मित्र सम्मानित

बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना की भी समीक्षा हुई। प्रदेश में अब तक 28,356 इकाइयों की स्थापना के लिए ऋण स्वीकृत हुए हैं, जबकि 24,883 इकाइयों को 1,040 करोड़ रुपये की अनुदान राशि वितरित की जा चुकी है। उत्कृष्ट कार्य के लिए उद्यमी मित्र इशानी श्रीवास्तव (बरेली), नेहा सिंह (सीतापुर) और अंशिल सिन्हा (बरेली) को प्रशस्ति-पत्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।